भिवाड़ी में पानी निकासी के समाधान के लिए राजस्थान व हरियाणा में सहमति बनी

मुख्यमंत्री भजनलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से यमुना जल समझौते पर विस्तृत चर्चा की

जयपुर, 24 जून। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच भिवाड़ी में पानी निकासी की समस्या के समाधान तथा यमुना जल समझौते की प्रगति पर फोन पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इस वार्ता के बाद यमुना जल लाने की महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत, इसी माह राजस्थान व हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से पाइपलाइन के लिए जमीनी अलाइनमेंट सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिए जाने की संभावना बनी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भिवाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में जल निकासी की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि प्राकृतिक बहाव हरियाणा की दिशा में होता है। इस संदर्भ में दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के अपशिष्ट जल के पूर्ण शोधन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त शोधित स्वच्छ जल का सदुपयोग सुनश्चित करने हेतु भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्षा काल में इस जल के साथ वर्षा जल भी मिल जाता है, जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है।

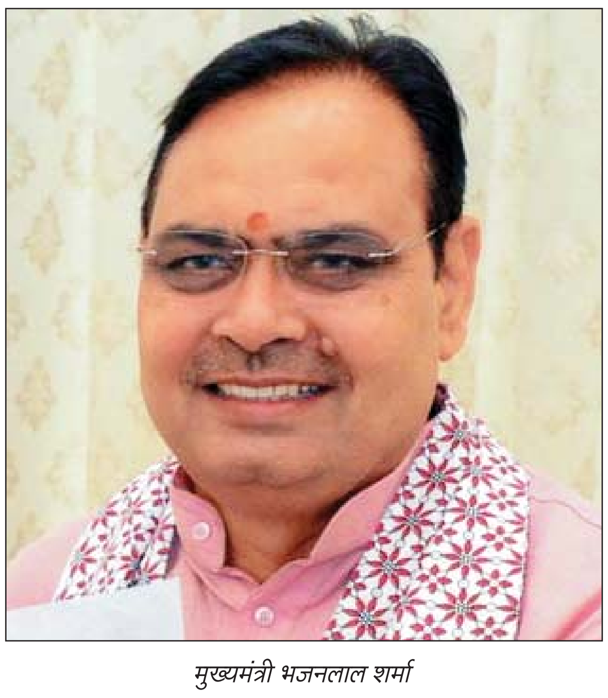

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवाड़ी क्षेत्र में वर्षा जल की निकासी एवं संग्रहण के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा 5 ऐसे बांधों की पहचान की गई है, जिनमें स्वयं के जलग्रहण क्षेत्र से वर्षा जल नहीं आता है, लेकिन इन्हें जल भण्डारण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। लगभग 250 एमसीएफटी भराव क्षमता वाली इस संग्रहण प्रणाली हेतु प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं उपादेयता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि भिवाड़ी क्षेत्र में वर्षा, जल की निकासी व संग्रहण के लिये जल संसाधन विभाग ने पांच ऐसे बाँधों की पहचान की है, जिनमें स्वयं के जलग्रहण क्षेत्र से वर्षा जल नहीं आता, लेकिन इनका जल भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हथनीकुंड बैराज से यमुना जल राजस्थान लाने की योजना पर भी चर्चा हुई। इस विषय पर पहले ही दोनों राज्यों के बीच संयुक्त डी.पी.आर. तैयार करने का समझौता हो चुका है। उन्होंने आगामी छह माह में डीपीआर तैयार कर इस काम की ठोस कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।

'चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव मतपत्र से नहीं हाथ उठाकर होगा'

चंडीगढ़, 24 जून। चंडीगढ़ नगर निगम की सियासत में 29 साल बाद बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अब मेयर चुनाव हाथ खड़े करके किया जाएगा। इसके साथ ही, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव गुप्त मतदान की बजाय शो ऑफ हैंड्स यानी हाथ खड़े करके किया जाएगा। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने निगम के एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला अनिल मसीह विवाद और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद लिया गया है। अगले मेयर चुनाव से यह नई प्रणाली लागू होगी।

- प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने निगम एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी।

इस बदलाव के लिए नगर निगम चंडीगढ़ (कार्यविधि और कार्य संचालन) विनियम, 1996 के विनियमन 6 में संशोधन किया गया है, जिसे गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को मंजूरी दी। वर्तमान में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं, जिसमें एक-एक करके पार्षद गुप्त वोट डालते हैं। अनिल मसीह कांड के बाद ये सवाल उठे थे कि जब 35 पार्षदों को ही वोट डालना है और वह सभी पार्षद किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में गुप्त मतदान क्यों कराया जाता है। इसकी जगह हाथ खड़े करके चुनाव कराने की मांग की गई।

ईरान-इज़रायल युद्ध के कारण 60 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द

रद्द फ्लाइट्स में जयपुर से उड़ान भरने वाली 6 फ्लाइट्स भी शामिल हैं

नई दिल्ली, 24 जून। ईरान-इजराइल युद्ध का असर भारत से मिडिल ईस्ट आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर पड़ रहा है। बढ़ते तनाव और एयरस्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। जयपुर एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इनमें मिडिल ईस्ट आने-जाने वाली 3-3 उड़ानें शामिल हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से अबु धाबी और शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइट को यूएई-कतर एयरस्पेस बंद होने से कैंसिल किया गया है।

अहमदाबाद एयरपोर्ट आने वाली 5 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। इनमें लंदन, अबु धाबी, दुबई, कुवैत और दोहा से आने वाली उड़ानें शामिल हैं। वहीं, अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली फ्लाइट एसजी-55 भी रद्द हुई है।

हालांकि अब एअर इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र धीरे-धीरे फिर से खुल रहे हैं, इसलिए एअर इंडिया आज से इस क्षेत्र के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी।

यूरोप से आने-जाने वाली उड़ानें, जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था, आज से धीरे-धीरे फिर से शुरू की जा रही हैं, जबकि अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट से आने-जाने वाली सेवाएं जल्द शुरू होंगी। दरअसल, 23 जून की रात को ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए कतर में अमेरिका के अल-उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दागीं। इसके बाद, कतर, बहरीन, यूएई, इराक और कुवैत ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। इंडिगो ने कहा है, जैसे-जैसे मिडिल ईस्ट के एयरपोर्ट दोबारा खुल रहे हैं, हम वहां के रूट्स पर अपनी सेवाएं सावधानीपूर्वक और धीरे-धीरे फिर से शुरू कर रहे हैं। पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रूट का चयन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद होने के कारण स्पाइसजेट कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।

- दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 48 फ्लाइट्स कैंसल हुई हैं तथा शेष फ्लाइट्स लखनऊ, अहमदाबाद और अमृतसर से रद्द की गई है।

मौजूदा स्थिति के कारण अकासा एयर की मिडिल ईस्ट जाने और वहां से आने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सभी उड़ानें केवल सुरक्षित एयरस्पेस में ही संचालित की जाएंगी।

उदयपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार, वह 22 जून को दिल्ली से उदयपुर घूमने आई थी और अंबामाता थाना क्षेत्र के एक होटल में ठहरी हुई थी। सोमवार शाम वह पार्टी के लिए निकली थी, जहां उस युवक से उसका परिचय हुआ। बातचीत के दौरान, युवक ने पहले दोस्ती जताई और फिर बहाने से अपने घर ले गया। युवती ने कई बार उसे होटल वापस छोड़ने को कहा, लेकिन युवक ने इंकार कर दिया। उसका मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, जिससे वह किसी से संपर्क नहीं कर सकी। अपार्टमेंट पहुंचने पर युवक ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती ने जब प्रतिरोध किया तो उसने बलपूर्वक दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई और वह किसी तरह निजी अस्पताल पहुंची। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के अनुसार, आरोपी युवक को चिन्हित कर लिया गया है तथा उसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

'अमेरिका की ''ट्रैवल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आतंकवाद के चर्चित नाम पाकिस्तान में शरण पा रहे हैं। उन्हें संरक्षण मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई सलाह जारी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा, भारत यात्रा के लिये तो एडवाइजरी जारी की जा रही है, और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन कर रहे हैं और ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक साथ रख कर बात कर रहे हैं! देखिए, हम दुनिया में कहां हैं और पाकिस्तान कहां है। मुझे बहुत अपमान महसूस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम जनरल आसिम मुनीर के साथ रखा जा रहा है। यदि आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगी कि वह उस सेना की वर्दी में एक आतंकवादी है। लेकिन यही हो रहा है और यही सबसे विडंबनापूर्ण बात है।

असलियत यह है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी शक्तियों को लुभाने में असामान्य समय बिताया है – गले लगाने से लेकर जबरदस्ती गले लगाने तक, 'हाउडी मोदी', 'नमस्ते ट्रंप', 'अबकी बार ट्रंप सरकार', अमेरिका में बिना बुलाए जाना, उन्होंने सब कुछ किया है। श्रीनेत ने कहा कि मैं देख रही हूं कि अमेरिका हमारे साथ ऐसे समय पर क्या कर रहा है, जब हमें विश्व की बड़ी शक्तियों का साथ चाहिए।

अमेरिका हमारे खिलाफ यात्रा एडवाइजरी जारी कर रहा है, उन घटनाओं को आधार बनाकर, जो विश्व के बाकी हिस्सों से संबंधित हैं, लेकिन यह वास्तव में हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सरकार इसके बारे में क्या कर रही है – बिल्कुल कुछ नहीं, हमेशा की तरह बिल्कुल सन्नाटा, एकदम चुप्पी।

श्रीनेत ने कहा, हकीकत यह है कि ट्रंप ने 17 बार युद्धविराम का श्रेय लिया है। उन्होंने हम पर टैरिफ लगाए। उन्होंने हमें ठग और धोखेबाज कहा। उन्होंने हमारे लोगों को हथकड़ी पहनाकर भारत वापस भेजा। वे लगातार हमें अपमानित कर रहे हैं और हमारी सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसलिए सवाल उठता है – हमारी विदेश नीति की कीमत क्या है? हमारी विदेश नीति की बुनियाद क्या है?

श्रीनेत ने सवाल उठाया, हमारी विदेश नीति की बुनियाद भारत के हितों को सर्वोपरि रखना है, लेकिन मोदी की विदेश नीति का मकसद कैमरा के सही एंगल के सामने खड़े होना है, ताकि वे दुनिया में जहां भी हों, अच्छे कैमरा एंगल से फोटो खिंचवा सकें। हमारे विदेश मंत्री लेज़र लाल आंखों के साथ रील्स बनाने में बहुत व्यस्त हैं। तो आप किससे उम्मीद करते हैं कि वह विदेश नीति को आगे बढ़ाएगा?

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बातचीत का निमंत्रण दिया

नयी दिल्ली, 24 जून। चुनाव आयोग ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को लेकर उनके किसी भी सवाल पर बातचीत के लिए पत्र लिख कर आमंत्रित किया है।

आयोग के सूत्रों ने यूनीवार्ता को बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों के मुद्दे पर इसी महीने की सात तारीख को एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित गांधी के लेख में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में आयोग ने उन्हें 12 तारीख को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, गांधी से कहा गया है कि आयोग महाराष्ट्र के चुनावों के बारे में कांग्रेस पार्टी की पहले की शिकायतों का विस्तृत उत्तर दे चुका है, जो आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। गांधी ने अपने सात जून के लेख में मोटे तौर पर उन्हीं मुद्दों को दोहराया है।

- आयोग ने राहुल गांधी के एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में उठाए मसलों पर वार्ता के लिए पत्र लिखा है।
- आयोग का दावा है कि राहुल गांधी के सभी सवालों का जवाब दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कोई संदेह है तो वे अपनी सुविधा से आकर बातचीत कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, आयोग ने गांधी को लिखा है कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर यदि सचमुच कोई शिकायत रही होंगी तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने उन्हें सक्षम न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर उठाया होगा। उन्होंने कहा, ' फिर भी विपक्ष के नेता के मन में कोई सवाल है तो आयोग उनके साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि और समय पर बैठ कर बातचीत करने को तैयार है।

महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव पिछले साल नवंबर में कराये गये थे। कांग्रेस ने मतदाता सूचियों और आखिरी घंटों में मतदान की तथाकथित तेज गति को लेकर कुछ सवाल उठाये थे। आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को इस पर विस्तृत जवाब दिया था। जवाब की प्रति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग का कहना है कि वह सभी चुनाव कानून-कायदे से कराता है और इस संबंध में जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करता है।

मंगलवार को इज़रायल से 326 भारतीय स्वदेश लौटे

नयी दिल्ली, 24 जून। ऑपरेशन सिंधु के तहत, इजरायल से मंगलवार को दो उड़ानों से 326 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ऑपरेशन सिंधु का इजरायल चरण 23 जून को शुरू हुआ, जिसमें इजरायल से 161 भारतीय नागरिकों का पहला समूह स्वदेश लौटा। आज सुबह 08:20 बजे जॉर्डन की राजधानी अम्मान से ये लोग सुरक्षित रूप से नयी दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरिटा उपस्थित थे। जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ही अम्मान से भारतीय वायुसेना के एक सी-17 विमान से आज सुबह करीब 8.45 बजे इज़राइल से 165 भारतीय नागरिक पालम वायुसैनिक हवाई अड्डे पर उतरे, जहां सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने उनका स्वागत किया।

'पूरा यूक्रेन हमारा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुनः स्थापित करना। जबकि पूर्ण अधिग्रहण शायद व्यावहारिक नहीं हो, उनकी रणनीति मिश्रित प्रभुत्व के पक्ष में हैं, जिसमें सैन्य धमकी, प्रॉक्सी सरकारें, आर्थिक दबाव और निरंतर सूचना युद्ध शामिल है। बेलारूस पहले से ही प्रभावी रूप से मॉस्को के अधीन है। मोल्दोवा ट्रांसनिस्ट्रिया में दबाव का सामना कर रहा है। जॉर्जिया के अलगाववादी क्षेत्र रूस के प्रभाव में हैं। यहां तक कि मध्य एशिया के कुछ हिस्से भी क्रेमलिन के बढ़ते प्रभाव में हैं।

पुतिन के लिए, युद्ध केवल ज़मीन के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचान, सभ्यता और इतिहास के बारे में है। रुस में यूक्रेन को पड़ोसी के रूप में नहीं, बल्कि साम्राज्य के एक खोए हुए हिस्से के रूप में देखा जाता है। उनकी यह घोषणा केवल एक भड़काऊ बयान नहीं है, बल्कि यह एक सिद्धांत है, जो क्षेत्रीय प्रभुत्व को फिर से हासिल करने का एक खाका है, जो भाईचारे और एकजुटता की आड़ में बनाया गया है।

स्कूल व्याख्याता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा, केन्द्र सरकार की एएसजी अर्चना पाठक और आरपीएससी की ओर से संस्कृति पाठक ने पक्ष रखा।

राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 23 जून को ही तीन विषयों की परीक्षाओं की तिथि पुनः निर्धारित कर दी है। ऐसे में अब परीक्षा को लेकर कोई टकराव नहीं रहा है और याचिकाकर्ताओं की शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं। इसलिए कोई अंतरिम आदेश देने की जरूरत नहीं है। यह भर्ती परीक्षा 2200 पदों के लिए प्रदेश के 21 शहरों में बनाए 904 परीक्षा केन्द्रों पर हो रही है। इसमें 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में कोई भी दखल ना केवल इसे प्रभावित करेगा, बल्कि आरपीएससी की अन्य 35 परीक्षाओं में भी देरी होगी। जबकि यूजीसी नेट परीक्षा साल में दो बार होती है, इसमें दिसंबर 2025 में भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए कोई भी अंतरिम आदेश देने की जरूरत नहीं है।

'प्रमुख हवाई अड्डों पर विमानन प्रणालियों में कई खामियां है'

नई दिल्ली, 24 जून। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से डीजीसीए द्वारा हर मोर्चे पर जांच की जा रही है। इस बीच विमानन नियामक डीजीसीए ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रमुख हवाई अड्डों पर की गई निगरानी में विमानन प्रणाली में कई खामियां पाई गई हैं। इन खामियों में, विमानों में दोबारा खामियों का आना और रनवे पर सेंटर लाइन मार्किंग का फीका पड़ जाना शामिल हैं। बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद की गई सर्विलांस में यह जानकारी सामने आई है। इसमें उड़ान संचालन, विमान की हवाई योग्यता, रनवे सुरक्षा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, संचार और नेविगेशन प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच की गई थी।

- डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संबंधित एयरलाइन कंपनियों के नामों का खुलासा किए बगैर एक बयान में कहा कि निगरानी में पाई गई खामियों के बारे में संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया गया है और उन्हें सात दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। डीजीसीए के संयुक्त महानिदेशक की अगुवाई में 2 टीमों ने दिल्ली और मुंबई सहित, प्रमुख हवाई अड्डों पर रात और सुबह के समय व्यापक निगरानी की। निगरानी के दौरान, एक घरेलू उड़ान को खराब टायरों के कारण रोक दिया गया था और आवश्यक सुधार के बाद ही इसे उड़ान भरने की अनुमति दी गई। डीजीसीए ने आगे बताया कि निगरानी में यह भी पाया गया है कि कई मामलों में विमानों में बार-बार खामियां देखने को मिल रही हैं, जो मॉनिटरिंग में कमी और अपर्याप्त सुधार की कमी को दर्शाती हैं। इसके अलावा, इस जांच में यह भी पाया गया है कि एक सिम्युलेटर विमान के कॉन्फिग्रेशन से मैच नहीं कर रहा था और सॉफ्टवेयर का वर्तमान वर्जन भी अपडेट नहीं था। बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा देखने को मिला था। इस हादसे में विमान सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, इस हादसे में कुल 297 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही डीजीसीए द्वारा लगातार उड़ानों के मद्देनजर सावधानियां बरती जा रही हैं।

लालू निर्विरोध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यादव ने सोमवार को निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र पूर्वे और सहायक निर्वाचन अधिकारी चितरंजन गगन के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उनके नामांकन का प्रस्ताव रखने वालों में पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी सहित कई अन्य प्रमुख नेता शामिल थे।

अब ईपीएफ से एक साथ 5 लाख रु. एडवांस लिए जा सकेंगे

नयी दिल्ली, 24 जून। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के लिए भविष्य निधि जमा से 'ऑटो सैटलमेंट' के माध्यम से अग्रिम राशि निकालने की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी है।

ईपीएफओ के सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि कोविड काल के दौरान एक लाख रुपए तक के अग्रिम दावे के लिए ऑटो सेंटलमेंट की सुविधा शुरू की गई थी, जिसे अब पांच लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इससे लाखों अंशधारकों को लाभ होगा।

ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इन्हीं पहलुओं को पुतिन ने बड़े आराम से नज़रअंदाज़ कर दिया। अंतरराष्ट्रीय ताकतों में, पुतिन ने ट्रंप की तीखी आलोचना की है, जबकि पश्चिमी यूरोपीय देशों ने ट्रंप को शांत करने की कोशिश की है।

रिपोर्टों के अनुसार, अयातुल्ला को राजधानी तेहरान से बाहर गहरे भूमिगत आश्रयों में ले जाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उनकी खुफिया एजेंसियों ने स्पष्ट रूप से यह पता लगा लिया है कि सर्वोच्च नेता को कहाँ छुपाया गया है, और बड़ी लापरवाही से उन्होंने यह भी कह दिया कि अयातुल्ला खामेनेई को ''जब चाहे हटाया जा सकता है।''

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी-कभी ईरान में शासन परिवर्तन का संकेत भी दिया है, लेकिन अपनी आदत के अनुसार, बाद में उसी बात का पूरी तरह खंडन भी कर दिया।

ईरान के भीतर राजनीतिक शक्ति संरचना को लेकर फिलहाल विभिन्न तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ ईरान विशेषज्ञों का मानना है कि त्वरित शासन परिवर्तन बेहद कठिन होगा, क्योंकि अयातुल्ला खामेनेई ने सरकार के लगभग हर पहलू पर अपनी गहरी पकड़ बना ली थी।

विदेशों में रहने वाले ईरानी लंबे समय से देश के शासन तंत्र और अपने ही नागरिकों पर उसके अति कठोर व्यवहार की आलोचना करते रहे हैं। खामेनेई शासन ने शासन तंत्र की आलोचना करने वालों और खासकर नागरिक स्वतंत्रता की माँग करने वालों पर निर्दयता से कार्रवाई की।

- एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि ईरान के ''एनरिच्ड यूरेनियम'' आदि को ज्यादा क्षति नहीं पहुँची है। अपने लंबे-चौड़े क्षेत्रफल में खामनेई ने अपना यह न्यूक्लियर सामान, सैकड़ों खड्डे खोदकर, पूरे देश में बिखेर रखा है और इज़रायल की सेना हर खड्डे को खोद कर नहीं देख सकती, न्यूक्लियर सामान नष्ट करने के लिए।

प्रवासी समुदाय पूर्व शाह, शाह ऑफ ईरान के बेटे राजा शाह द्वितीय की सत्ता में वापसी के लिए अभियान चलाता रहा है। लेकिन ईरान के भीतर इन लोगों के पास लगभग कोई जनाधार नहीं है। मौजूदा सरकार बेहद अलोकप्रिय है, फिर भी देश की लगभग बीस प्रतिशत जनता उसका समर्थन करती है, और सरकार के प्रति अत्यधिक समर्पित है।

सत्ता में आने के बाद, अयातुल्ला खामेनेई ने रणनीतिक रूप से अपने लोगों को सेना और अन्य प्रमुख संस्थानों में नियुक्त किया। परिणामस्वरुप, भले ही वे देश की उच्च वर्ग और मध्यवर्ग में अलोकप्रिय रहे हों, वर्षों तक, वे हर प्रकार के विरोध को कुचलते रहे हैं।

खामेनेई का सत्ता में आना और लंबे समय तक सत्ता में बने रहना, उनकी नेतृत्व क्षमता और आत्म रक्षा की रणनीति को दर्शाता है। वे एक गरीब धार्मिक विद्वान के बेटे थे और विभिन्न विरोधों के बावजूद, जिसमें प्रमुख इस्लामी विद्वानों का विरोध भी शामिल था, उन्होंने अपने लिए जगह बनाई।

उन्हें एक साधारण स्तर का विद्वान माना जाता था और उनकी धार्मिक राय को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन उन्होंने सेना के उच्च अधिकारियों से वर्षों में मजबूत संबंध बनाए और आज भी उनके बीच खामनेई का समर्थन आधार बहुत मजबूत है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि मौजूदा सर्वोच्च नेता को हटाया जाता है, तो जो लोग सत्ता में आएंगे, वे और भी ज़्यादा कट्टर और देश की जनता के साथ ज्यादा निर्दयी हो सकते हैं।

यहाँ तक कि, संकेत ये भी मिल रहे हैं कि खामेनेई ने अपनी मृत्यु की स्थिति में अपने उत्तराधिकारी के रूप में तीन नेताओं को नामित किया है। तथापि, ये तीनों भी उन्हीं की तरह की विचारधारा वाले हैं।

कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि देश पर भारी हमले और हमलों को लेकर आई सीमित प्रतिक्रिया के बाद, ईरान और क्या कर सकता था, देश की सैन्य संरचना में कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि ये कट्टरपंथी ताकतें भविष्य में किसी भी प्रकार के उदारीकरण और बाहरी दुनिया के लिए ईरान को खोलने के खिलाफ होंगी। जहाँ तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात है, तो यह सोचना सही नहीं होगा कि सब कुछ नष्ट हो चुका है और ईरान के पास अब समृद्ध यूरेनियम का भंडार नहीं है, जो हथियार निर्माण की मूल सामग्री है। इतने वर्षों से अपने परमाणु केन्द्रों पर मंडरा रहे खतरों को देखते हुए, ईरानियों के लिए यह मूर्खता होती कि वे सारा कीमती भंडार एक ही स्थान पर या केवल घोषित केन्द्रों में रखते।

एक विशाल देश होने के नाते, उन्होंने अपने संसाधनों को देशभर में फैले गहरे भूमिगत स्थानों में छिपाकर रखा होगा। यह असंभव बात है कि वर्तमान हमलों के बाद उनकी परमाणु क्षमता पूरी तरह नष्ट हो गई हो। निश्चित रूप से किसी हद तक बची हुई होगी।

हाँ, उनकी समग्र बुनियादी संरचना को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है और अब दशकों तक इसकी पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए भारी परिश्रम करना होगा। अब जो देश के साथ हुआ है, उसके बाद यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।

एक्सिओम मिशन के तहत आज अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे शुभांशु

चेन्नई, 24 जून। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 25 जून को एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) रवाना होंगे। एक्सिओम-4 बुधवार को स्थानीय समय के अनुसार तड़के 2.31 बजे अमेरिका से उड़ान भरेगा। एक्सिओम-4 गुरुवार सुबह सात बजे आईएसएस पर पहुंचेगा। इसके तहत, चार सदस्यीय चालक दल 14 दिनों के मिशन पर होगा और लगभग 60 अनुसंधान करेगा। इस दल के आईएसएस में रहने के दौरान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा किए जाने वाले सात प्रयोग शामिल हैं।

- एक्सिओम -4 भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के ढाई बजे अमेरिका से रवाना होगा और सुबह 7 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेगा।

'संस्कृत को करोड़ों रूपए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्य पांच शास्त्रीय भाषाओं के लिये किये गये कुल आवंटन 147.56 करोड़ रुपये से 17 गुना अधिक हैं।

राज्य की अपनी कई यात्राओं के दौरान और, यहां तक कि, संयुक्त राष्ट्र में भी मोदी ने यह दावा किया था कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है और केन्द्र सरकार ने ''काशी तमिल संगमम'' का आयोजन किया था, लेकिन द्रमुक और उसके सहयोगियों ने इस प्रयास को खारिज किया और भाजपा के इस प्रयास को राजनीतिक लाभ की कोशिश बताया।

इसके अलावा, राज्य की द्रमुक सरकार ने तीन भाषा सूत्र, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) की आधारशिला है, का दृढ़ विरोध किया है। चूंकि तमिलनाडु में मातृभाषा (तमिल) और अंग्रेजी का दो-भाषा सूत्र पहले से ही चल रहा है, उसने एनईपी को खारिज कर दिया है तथा इसे पीछे के दरवाजे से हिन्दी को थोपने का साधन बताया है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सलेम में एक सरकारी कार्यक्रम में 1649.18 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और नई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए, मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार जानबूझकर कीलडी की खुदाई रिपोर्ट और लोहे की प्राचीनता संबंधी खबरों को नकारने की कोशिश कर रही है, जो यह घोषित करती हैं कि लोहे का युग तमिलनाडु से शुरू हुआ था।

उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा, ''केन्द्रीय मंत्री शेखावत द्वारा कीलडी में खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों के और अधिक वैज्ञानिक प्रमाणीकरण की मांग करना मदुरै की प्राचीनता को नकारने जैसा है। उन्होंने उस रिपोर्ट पर फिर से काम किये जाने की मांग की है, जिसे आवश्यक वैज्ञानिक डेटा प्राप्त करने के बाद संकलित किया गया था। हमने तमिलनाडु में लोहे की प्राचीनता की घोषणा करने से पहले, विश्व की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराये थे तथा उसके बाद रिपोर्ट जारी की थी। इसके लिए बधाई देना तो दूर रहा, केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकार तक नहीं किया तथा इस पर एक शब्द तक नहीं कहा है। इसके बजाय वे तमिलों की प्राचीनता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं।''

इसके बाद, उन्होंने अन्नाद्रमुक के महासचिव के. पलानीस्वामी (ईपीएस) पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के क्रोध से डरते हुए, वे इन मुद्दों को उठाने का साहस नहीं रखते। स्टालिन ने कहा, ''उन्होंने स्वार्थपूर्ण निजी हितों की रक्षा के लिए पार्टी को गिरवी रख दिया है, तो वे कैसे बोल सकते हैं?

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री और भाजपा के मजबूत नेता अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया, उनसे यह पूछते हुए कि वे ऐसी एक परियोजना बता दें, जो भाजपा ने मोदी सरकार के 11 वर्षों में तमिलनाडु को लाकर दी हो।

उन्होंने कहा, ''माननीय शाह, क्या आपने अपनी मदुरै यात्रा के दौरान उस एआईआईएमएस (एम्स) अस्पताल का दौरा किया था, जिसकी घोषणा 11 साल पहले केन्द्रीय बजट में की गई थी? क्या यह एक अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र है, जो 10 साल से निर्माणाधीन है? अगर फंड्स आवंटित कर दिये गए होते, तो एम्स दो वर्षों में बनकर तैयार हो गया होता, और आप हमारी आलोचना कर रहे हैं।''

''द्रमुक सरकार ने पिछले चार वर्षों में मदुरै के आसपास अत्याधुनिक कलैग्नर शताब्दी पुस्तकालय, जल्लीकट्टू परिसर और कीलडी संग्रहालय बनवाए हैं,'' उन्होंने कहा कि द्रविड़ मॉडल और भाजपा मॉडल के बीच यही अन्तर है।

महाराष्ट्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिनट मंत्रियों और मुख्यमंत्री के साथ ईमेल के जरिए साझा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेजों को सीधे आईपैड पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने के लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों को 1.6 करोड़ रुपये में आईपैड वितरित करने का फैसला किया था।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908